भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्य सभा

13.03.2026 के

अतारांकित प्रश्न सं. 2513 का उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेल अवसंरचना के लिए कुल बजटीय आवंटन

2513. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्यः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर पूर्वी रेलवे सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेल अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में कुल कितना बजटीय आवंटन किया गया है;

(ख) इस आवंटन का राज्य-वार और परियोजना-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में चल रही प्रमुख और नई रेलवे परियोजनाओं में अब तक की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग):

पूर्वोत्तर क्षेत्र रेल बजट:

पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के अंतर्गत आते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है:-

अवधि	परिव्यय
2009-14	2,122 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2025-26	10,440 करोड़ रुपए (लगभग 5 गुना)

रेलपथ निर्माण:

वर्ष 2009-14 और 2014-2025 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाले नए रेलपथ के निर्माण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

अवधि	कमीशन किए गए नए रेलपथ	नए रेलपथों की औसत कमीशनिंग
2009-14	333 किलोमीटर	66.6 किलोमीटर प्रतिवर्ष
2014-25	1,840 किलोमीटर	167.27 किलोमीटर प्रतिवर्ष (लगभग 2.5 गुना)

स्वीकृत की गई परियोजनाएं:

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुल लंबाई 777 किलोमीटर और 69,342 करोड़ रुपए की लागत की 12 रेल परियोजनाएं (08 नई लाइनें, 04 दोहरीकरण) हैं, को स्वीकृत किया गया है। जिसका सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइनें	08	448	113	38,078
दोहरीकरण/बहुपथन	04	329	165	3,598
कुल	**12**	**777**	**278**	**41,676**

हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कमीशन की गई परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रुपए में)
1	अगरतला-सबरूम नई लाइन (112 किलोमीटर)	3,170
2	अगरतला-अखौरा नई लाइन (5 किलोमीटर)	865
3	रंगिया-मुरकोंगसेलेक आमान परिवर्तन (510 किलोमीटर)	3,019
4	कुमारघाट-अगरतला आमान परिवर्तन (109 किलोमीटर)	1,242
5	लामडिंग-बदरपुर-सिलचर और बदरपुर-कुमारघाट आमान परिवर्तन (412 किलोमीटर)	6,500
6	लमडिंग-होजाई दोहरीकरण (45 किलोमीटर)	410
7	दिगारू-होजाई दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	1,873
8	न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी दोहरीकरण (143 किलोमीटर)	2,048
9	बोगीबील पुल (92 किलोमीटर)	5,820

इसके अलावा, सीमावर्ती राज्य मिजोरम को राजधानी से संपर्कता प्रदान करने के लिए, बइरबी - सायरंग (51.38 कि.मी.) नई लाइन परियोजना हाल ही में सितंबर, 2025 में पूरी की गई और चालू की गई है। इस परियोजना में क्षेत्र में कठोर भूभाग और जटिल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों के माध्यम से निर्मित 45 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 88 छोटे पुल शामिल हैं।

इस परियोजना के पूरा होने के साथ ही गुवाहाटी, नाहरलागुन (ईटानगर के लिए) और अगरतला के बाद आइजोल चौथा पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी बन गया है जो भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। मिजोरम में सायरंग से आगे की संपर्कता प्रदान करने के लिए, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सायरंग - हबिचुआह (223 कि.मी.) नई लाइन के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण स्वीकृत किया गया है।

चालू परियोजनाएं:

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली शुरू की गई कुछ मुख्य परियोजनाएँ निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	**परियोजना का नाम**	**लागत (करोड़ रुपए में)**
1	जिरीबाम-इंफाल नई लाइन (111 किलोमीटर)	21,886
2	दीमापुर-कोहिमा नई लाइन (82 किलोमीटर)	15,230
3	मुरकोंगसेलेक - पासीघाट नई लाइन (27 किलोमीटर)	1,249
4	न्यू बंगाईगाँव-गोआलपाड़ा - गुवाहाटी (कामाख्या) दोहरीकरण (176 किलोमीटर)	4,962
5	सरायघाट पुल का दोहरीकरण (7 किलोमीटर)	1,474
6	कामाख्या गुवाहाटी तीसरी लाइन (6 किलोमीटर)	395
7	लामडिंग - फुरकेटिंग दोहरीकरण (140 किलोमीटर)	2,124
8	फरकाटिंग - तिनसुकिया दोहरीकरण (194 किलोमीटर)	3,634

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में पड़ने वाले कुल 3,590 किलोमीटर लंबाई के 45 सर्वेक्षण कार्यों (24 नई लाइन, और 21 दोहरीकरण) को मंजूरी दी गई है।

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वानिकी संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ

- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए एक वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

रेल परियोजनाओं के प्रभावी और तीव्र कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में निम्नानुसार शामिल हैं:

- निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि।
- फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी।
- शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन और वन्यजीव संबंधी स्वीकृति के लिए और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

****